अफगानिस्तान में, अमरीका में, इंग्लैंड में और कनाडा में सिखों के साथ निरंतर ज्यादती हो रही है, कत्ले-आम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और नस्ली भेदभाव हो रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि जो वहां पर हमारी एम्बैसीज़ हैं, वे वहां क्या कर रही हैं और हमारी सरकार सब कुछ क्यों चुपचाप देख रही है? मैं सरकार से यह रिक्वेस्ट करुंगा कि कृपया इसमें सरकार दखल दे और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ...(**समय की घंटी**)... दुनिया के किसी भी मुल्क में जहां सिख रह रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन एन्श्योर करवाए। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री विजय गोयल।

Future of E-Rickshaws in Delhi

श्री विजय गोयल (राजस्थान): उपसभापति जी, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें दो लाख लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है। ये लोग दिल्ली से बाहर के प्रदेशों से आए हैं। ये लोग पिछले दिनों से बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा चला रहे थे। पिछले दस दिनों से इनके घरों में चूल्हा नहीं जला है, क्योंकि इनके ऊपर टोटल प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब दिल्ली के अंदर सौ रिक्शे आए थे, तब इनको किसी ने नहीं रोका, जब ये हजार हुए, तब किसी ने नहीं रोका, जब दस हजार हुए, तब भी किसी ने नहीं रोका, लेकिन अब, जबकि 1 लाख से लेकर 2 लाख ई-रिक्शों से लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और जब तक हाई कोर्ट में कोई निश्चित फाइनल फैसला हो, उससे पहले इनको कोई temporary relief मिलना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Delhi Government has to approach the High Court.

श्री विजय गोयल: उपसभापति जी, हाई कोर्ट की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस बीच में यह मैसेज आया था कि जब तक कोई फैसला हो, तब तक सरकार इस बात के लिए प्रयत्न करे कि इनको temporary लाइसेंस दे दिया जाए, इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, क्योंकि यह रोजी रोटी का सवाल है और इससे लाखों परिवार जुड़े हैं। ये सभी लोग बाहर से यहाँ इसलिए भी आए, क्योंकि इनको लगता था कि ये यहाँ पर रोजगार ढूंढ लेंगे। सरकार ने इसकी दो कमेटीज़ भी बनाई हैं, लेकिन वे कमेटीज़ अभी तक उसके रूल्स एंड रेग्युलेशन्स फाइनल नहीं कर पाई हैं। मैं यह गुहार लगाना चाहता हूं कि इस समस्या का तुरंत कोई temporary हल निकालना चाहिए। मैं आपके समक्ष यही बात रखना चाहता हूं कि इन लोगों के ऊपर बहुत मुसीबत आई हुई है।

SHRI K. N. BALAGOPAL (Kerala): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्री रामदास अठावले (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्रीमती बिमला कश्यप सूद (हिमाचल प्रदेश)**:** उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

कुछ माननीय सदस्य: उपसभापति जी, हम स्वयं को इससे संबद्ध करते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Actually, battery-operated rickshaws should be encouraged because they are pollution -free. I think you should take it up with the Government.

श्री विजय गोयल: ये पॉल्यूशन फ्री हैं। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी, कैम्पस, छोटे-छोटे इलाकों या छोटी दूरी के डेस्टिनेशन्स पर थ्री व्हीलर्स से काफी सस्ते पड़ते हैं। ये पॉल्युशन फ्री हैं, एन्वायरन्मेंट फ्रेंडली हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को तुरंत इसका हल निकालना चाहिए। लीडर ऑफ दि अपोजिशन एंड लीडर ऑफ दि हाउस बैठे हैं, वे इसका हल बता देंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think the Government should examine as to what can be done. Something has to be done. It is a question of livelihood of more than one lakh people.

Bad maintenance of Government websites

SHRI K.N. BALAGOPAL (Kerala): Sir, I would like to bring the issue of poor maintenance of Government websites before this august House. Many Government websites are not properly updated. There are many sites in which links are not connected to concerned pages. Many times it happens with our Rajya Sabha website.

Sir, websites are an important link between the Government and the general public. E-mail, Fax numbers, telephone numbers, etc., given in various websites are not correct. Proper updation is not taking place. New Government has come, but in many websites, the names of the Ministers are not updated. I am not giving all the details. The names of officers, who are dealing with particular departments, are not given. Their phone numbers are not there.

Sir, people throughout the world use websites to get details for their work. To interact with the Government, a website is very important for the people, especially those who are working in foreign countries. They need the details to contact the embassy people. Rajya Sabha website is one of the good websites. Even in that, the link which takes you to other sites, is not properly working. If we take the case of other areas, even websites of many PSUs are not properly working.

Sir, we need a thorough re-look into that and their updation is needed. Some discussion format should be given there. Proper contact number should be given there.

We have had a very serious discussion in the House on language questions of the Civil Service Examination. Official website should give all the details. But the basic data relating to the Government of India should be given in the scheduled languages. I am not talking about all the forms. But for a worker, who is working in Gulf area, things like how to apply for renewal of passport and visa, these should be given in every language given in the Schedule. This is my request and website should be updated properly.